

Statement*Prices recommended by Agricultural Prices Commission for 1979-80 (Estimated)*

Variety	(Rs per quintal)	
	Paddy	Coarse grains
Common	90	85

Prices demanded by State Governments

Name of State	Variety of Paddy	(Rs per quintal)	
		Paddy	Coarse grains
Punjab	IR 8	94	
	PR 106	109	110 for maize
Haryana	IR 7/Ban	96	121 for Bajra
	Punjab	105	141 for maize
	Punjab	121	
Uttar Pradesh	Paddy	91	90
Andhra Pradesh	Common/Coarse	120	
Tamil Nadu	Coarse	130	
Orissa	,	100	85
Madhya Pradesh	,	125	125
Gujarat	,	100	90 for maize
Rajasthan	,	90	90

आपरेसन फ्लड-2 के अधीन बटर आयल, बनस्पति तेल तथा खाद्य पदार्थ

102. श्री शोम प्रकाश शर्मा
डा० रामजी सिंह
श्री सी० के० चन्द्रप्यन

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आपरेसन फ्लड-2 के अन्तर्गत भारत को विदेशों से कितने मस्य का बटर आयल, बनस्पति तेल तथा अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त होने की आशा है,

(ख) क्या इन पदार्थों के अधिवाधिक उपयोग के लिये अथवा अधिक डेरियां स्थापित करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है और

(ग) उक्त योजना से राज्य-वार किनने राष्ट्रीय लोगों को लाभ पहुंचने की आशा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय आपरेसन फ्लड-2 के लिये उपहार स्वरूप केवल 1,86,000 मीटरी टन रिकम दुग्ध चूर्ण तथा 76,200 मीटरी टन बटर आयल दान देने के लिये सहमत हुआ है। विदेशों से आपरेसन फ्लड-2 के तहत अन्य बाई खाद्य सामग्री प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है। कार्यक्रम के अन्तर्गत इन जिल्लों के पुनर्निर्माण द्वारा 206 करोड़ रुपये की धनराशि सुचित होने की आशा है।

(ख) जी हाँ। राष्ट्रीय डेरी परियोजना का आपरेसन फ्लड-2 तैयार किया गया है और इस परियोजना को उपर्युक्त जिल्लों से पुन तैयार किये गये दूध की बिनी से आंशिक रूप से आर्थिक सहायता दी जागी।

(ग) कृषक परिवारों की संख्या के बारे में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य का नाम	कृषक परिवारों की संख्या
1. जम्मू तथा कश्मीर	1,30,000
2. पंजाब	8,50,000
3. हिमाचल प्रदेश	1,85,000
4. हरियाणा	5,50,000
5. राजस्थान	14,30,000
6. उत्तर प्रदेश	14,45,000
7. महाराष्ट्र	4,45,000
8. गुजरात	11,80,000
9. मध्य प्रदेश	2,90,000
10. कर्नाटक	8,25,000
11. तमिलनाडु	2,65,000
12. आंध्र प्रदेश	9,30,000
13. बिहार	8,20,000
14. पश्चिम बंगाल	5,75,000
15. अरुणाचल प्रदेश	2,25,000

सीरायू के कोलकी टेलीफोन एक्सचेंज में अनिर्णीत टेलीफोन कनेक्शन

103. श्री धर्म सिंह झाई पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सीरायू क्षेत्र में राजकोट जिले के उपलेटा तालुक में नागबदर गांव के दो टेलीफोन कनेक्शनों की मांग कोलकी टेलीफोन एक्सचेंज में अनिर्णीत पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो ये कब से अनिर्णीत है और इसके लिये कहाँ और कितनी धनराशि जमा की गई है ;

(ग) नागबदर के लोगों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जायेंगे जिनके आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(घ) उन्हें टेलीफोन कनेक्शन देने में किन कारणों से विलम्ब किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सरहूरि प्रसाद कुबेरच साह) : (क) जी हां।

(ख) दो कनेक्शन क्रमशः तारीख 21-3-78 और 18-12-78 से अनिर्णीत पड़े हैं। उपरोक्त तारीखों को दोनों व्यक्तियों ने 800 रुपये उपलेटा डाकघर में जमा कराये थे।

(ग) और (घ). ये लम्बी दूरी के कनेक्शन हैं जिसके लिये भारी मात्रा में लाइन स्टोर की आवश्यकता है जो उपमहल घोरजी में आवश्यक लाइन स्टोर उपलब्ध होने पर ही लम्बी दूरी के कनेक्शन के लिये अनिर्णीत पड़ी हुई प्रतीक्षा सूची में उसकी भारी आने पर ही उपलब्ध हो सकेगा।

Admission in Universities and Schools in big Cities

104. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of EDUCATION SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the problem of admission to Universities and Schools in big cities has been assuming serious proportions; and

(b) if so, the steps taken by the Government to ease the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI-MATI RENUKA DEVI BARAKA-TAKI): (a) and (b) The problem of admission to Universities and schools in big cities is not only of numbers but more in respect of preference for particular institutions and particular courses, the students themselves not necessarily having the requisite educational attainments. The universities prescribe minimum requirements for admission to the various courses in the university teaching departments and colleges, and subject to the limitation of seats in different courses in each institution, candidates fulfilling the minimum requirements are normally admitted. Besides, a large number of universities have provision for correspondence courses and also allow candidates to appear privately at their examinations.

It is primarily the responsibility of the State Governments/Union Territories to provide facilities for school